भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1487
मंगलवार, 9 दिसंबर, 2025/18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियां

1487.श्रीमती रुचि वीराः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में विशेष रूप से कृषि ऋण, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में सहकारी समितियों की स्थिति और कार्यप्रणाली, उनके प्रबंधन और वित्तीय स्थिति तथा उनके सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा उक्त सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए संस्थागत सुधार, बेहतर विनियामक निगरानी और बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को निरंतर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी हाँ मान्यवर । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल 40,665 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 22,731 समितियां कार्यशील हैं । क्षेत्रवार और जिलेवार, सहकारी समितियों की कुल संख्या और कार्यशील समितियों की संख्या क्रमशः **संलग्नक-1 और संलग्नक -2** के रूप में संलग्न है ।
(ख) उत्तर प्रदेश सहित देशभर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । ब्योरा **संलग्नक** -3 में दिया गया है ।

इसके अलावा, दिनांक 25.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने देश भर में सहकारी संस्थानों के विकास के लिए 4,67,455.66 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं जिसमें से 7,646.11 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में सहकारी विकास के लिए संवितरित किए गए हैं । मुरादाबाद जिले के लिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना के

अंतर्गत दिनांक 22.02.2014 से 30.6.2018 के दौरान एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (ICDP) लागू की है और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की हैः -

(लाख रु. में)

ऋण	**अल्प विकसित सब्सिडी**	**परियोजना कार्यान्वयन टीम सब्सिडी**	**कुल**
858.41	146.847	74.813	1080.070

(ग) सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के सामने आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से "सहकार-से-समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए कई पहलें की हैं। इन प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- मानकीकृत सॉफ्टवेयर, डिजिटल लेखांकन, ऑनलाइन सेवा प्रदाय और बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना उत्तर प्रदेश सहित देश भर में 79,630 से अधिक पैक्स को कवर करती है ।
- पैक्स की आदर्श उपविधियां , भंडारण, प्रसंस्करण, एलपीजी वितरण और कॉमन सेवा केंद्रों जैसे कार्यकलापों के विविधीकरण, बेहतर शासन मानकों को सुनिश्चित करने और सदस्य-केंद्रित संचालन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती हैं ।
- पैक्स अधिकारियों को डिजिटल संचालन, वित्तीय प्रबंधन और सेवा प्रदाय में प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।
- त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना को सशक्त करना, पैक्स, DCCBs और StCBs के बीच समन्वय में सुधार करना, बेहतर तरलता प्रबंधन और ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।
- सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रित अन्न भंडारण योजना।
- त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना।

*****

संलग्रक -1

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार कुल सहकारी समितियां और कार्यशील सहकारी समितियां

क्रम सं	क्षेत्र	समितियों की संख्या	कार्यशील समितियों की संख्या
1	कृषि एवं संबद्ध सहकारी समिति	1240	718
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	1829	115
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	0	0
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	1004	473
5	क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट समिति	2255	1186
6	डेयरी सहकारी समिति	16199	7664
7	शैक्षिक और प्रशिक्षण सहकारी समितियां	6	6
8	मात्स्यिकी सहकारी समिति	1589	1266
9	हस्तशिल्प सहकारी समिति	26	0
10	हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	1814	886
11	आवासन सहकारी समिति	3247	1207
12	जूट और कॉयर सहकारी समिति	0	0
13	खादी ग्रामोद्योग समिति	148	148
14	श्रमिक सहकारी समिति	551	138
15	पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति	19	0
16	विपणन सहकारी समिति	1807	892
17	विविध ऋण सहकारी समिति	6	6
18	विविध गैर क्रेडिट	70	7
19	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	129	69
20	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS)/FSS/ LAMPS	8439	7765
21	रेशम उत्पादन सहकारी समिति	88	87
22	सामाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारिता	2	1
23	चीनी मिल सहकारी समिति	27	27
24	पर्यटन सहकारी समिति	1	1
25	परिवहन सहकारी समिति	85	6
26	जनजीय-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति	0	0
27	शहरी सहकारी बैंक (UCB)	56	51
28	महिला कल्याण सहकारी समिति	28	12
	कुल	**40665**	**22731**

स्रोत: दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार NCD

संलग्नक -2

उत्तर प्रदेश में जिलेवार कुल सहकारी समितियां और कार्यशील सहकारी समितियां

क्रम सं.	जिले का नाम	समितियों की संख्या	कार्यशील समितियों की संख्या
1	आगरा	1,287	616
2	अलीगढ़	518	307
3	अम्बेडकर नगर	641	465
4	अमेठी	347	186
5	अमरोहा	353	193
6	औरैया	409	104
7	अयोध्या	618	409
8	आजमगढ़	1,026	686
9	बागपत	296	226
10	बहराइच	539	310
11	बलिया	442	251
12	बलरामपुर	194	133
13	बांदा	352	169
14	बाराबंकी	767	455
15	बरेली	821	533
16	बस्ती	563	401
17	भदोही	197	122
18	बिजनौर	774	436
19	बदायूं	524	277
20	बुलंदशहर	717	554
21	चंदौली	542	265
22	चित्रकूट	339	193
23	देवरिया	403	269
24	एटा	429	209
25	इटावा	498	103
26	फर्रुखाबाद	498	132
27	फतेहपुर	714	237
28	फिरोजाबाद	303	134
29	गौतम बुद्ध नगर	558	196
30	गाजियाबाद	713	218
31	गाजीपुर	859	441
32	गोंडा	739	445
33	गोरखपुर	788	480
34	हमीरपुर	335	247
35	हापुर	293	204
36	हरदोई	601	377
37	हाथरस	219	163
38	जालौन	589	237
39	जौनपुर	687	371

क्रम सं.	जिले का नाम	समितियों की संख्या	कार्यशील समितियों की संख्या
40	झांसी	695	224
41	कन्नौज	363	69
42	कानपुर देहात	473	118
43	कानपुर नगर	966	397
44	कासगंज	146	107
45	कौशाम्बी	470	145
46	खेरी	456	351
47	कुशी नगर	350	223
48	ललितपुर	343	209
49	लखनऊ	1,390	718
50	महाराजगंज	373	217
51	महोबा	208	98
52	मैनपुरी	245	125
53	मथुरा	532	462
54	मऊ	445	176
55	मेरठ	864	708
56	मिर्जापुर	633	407
57	मुरादाबाद	870	507
58	मुजफ्फरनगर	420	343
59	पीलीभीत	381	284
60	प्रतापगढ़	525	341
61	प्रयागराज	1,333	660
62	रायबरेली	733	511
63	रामपुर	379	254
64	सहारनपुर	749	478
65	संभल	286	185
66	संत कबीर नगर	217	148
67	शाहजहाँपुर	581	435
68	शामली	173	94
69	श्रावस्ती	237	97
70	सिद्धार्थ नगर	380	196
71	सीतापुर	685	472
72	सोनभद्र	207	147
73	सुल्तानपुर	507	309
74	उन्नाव	583	363
75	वाराणसी	975	399
	कुल	**40,665**	**22,731**

स्रोत: दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार NCD पोर्टल

संलग्नक-3

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत जारी निधि

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1	महाराष्ट्र	87.95	33.65	-	9.14	130.73
2	राजस्थान	23.78	43.3	11	6.76	84.83
3	गुजरात	-	58.3	22.19	13.48	93.97
4	**उत्तर प्रदेश**	**11.28**	**42.3**	**-**	**13.51**	**67.1**
5	कर्नाटक	40.25	15.39	-	12.19	67.83
6	मध्य प्रदेश	33.23	25.42	-	7.78	66.43
7	तमिलनाडु	33.2	12.48	-	6.05	51.73
8	बिहार	32.95	-	14.66	4.15	51.76
9	पश्चिम बंगाल	30.54	-	-	15.25	45.79
10	पंजाब	25.52	-	-	7.42	32.94
11	आंध्र प्रदेश	14.93	3.74	14.54	2.1	35.31
12	छत्तीसगढ़	14.86	-	10.21	3.28	28.35
13	हिमाचल प्रदेश	9.56	7.32	3.09	6.77	26.74
14	झारखंड	10.99	-	-	8.21	34.3
15	हरियाणा	4.85	2.44	-	-	8.79
16	उत्तराखंड	-	-	-	-	-
17	असम	6.41	2.45	6.39	1.76	17.02
18	जम्मू और कश्मीर	5.25	1.52	1.85	1.75	10.37
19	त्रिपुरा	2.95	1.13	3.03	-	-
20	मणिपुर	2.55	-	-	-	3.14
21	नागालैंड	0.36	2.46	1.6	0.01	4.43
22	मेघालय	1.23	-	-	-	2.34
23	सिक्किम	1.18	0.9	0.79	0.41	3.28
24	गोवा	0.32	0.13	0.44	0.31	1.19
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-
26	पूड्डुचेरी	0.44	0.17	-	-	0.67
27	मिजोरम	0.27	-	-	0.56	1.27
28	अरुणाचल प्रदेश	0.15	0.12	0.09	-	-
29	लद्दाख	-	-	-	-	0.12
30	ओडिशा	-	-	-	-	18.07
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	-	-	-	-	-
32	कुल	395	257.71	105.54	142.24	900.49
33	नाबार्ड	100	40.92	25	-	165.92
	कुल	**495**	**298.63**	**130.54**	**-**	**1,066.41**

नोट: दिनांक 25.11.2025 तक का डेटा